Neutral Citation

2022:CGHC:14274



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका क्रमांक 3754/2021**

1. शुभम डे पिता श्री गोपी डे, उम्र-23 वर्ष,

निवास-दुर्गानगर लींगयादीह, तहसील-बिलासपुर

थाना सरकंडा जिला-बिलासपुर छ.ग.

**.....अपीलार्थी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**विरुद्ध**

1. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी ऐजुकेशन (सीबीएसई)

द्वारा चेयरमेन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी ऐजुकेशन

हेडक्वाटर शिक्षा केन्द्र -2 कम्यूनिटी सेन्टर,

प्रीत विहार दिल्ली 110092.

2. सचिव सेकेन्डरी बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी

ऐजुकेशन (सीबीएसई) रीजनल ऑफिस प्लाट नंबर-04

शैलश्रीविहार, चंद्रशेखर उर्फ भुनेश्वर

जिला-कुरदा( ओडिसा)

3. सह-सचिव(M and M) सेकेन्डरी बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड

ऑफ सेकेन्डरी ऐजुकेशन (सीबीएसई)

रीजनल ऑफिस प्लाट नंबर-04 शैलश्रीविहार,

चंद्रशेखर उर्फ भुनेश्वर जिला-कुरदा (ओडिसा).

4. प्रींसपिल लोयला स्कूल, राजिम विहार SECL

जिला-बिलासपुर छ.ग.

**.....प्रत्यर्थीगण**

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिये - श्री चंद्रेस श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक 01 से 03 के लिये - श्री टी.के.तिवारी अधिवक्ता ।

---

**माननीय न्यायमूर्ति श्री पी० साम कोसी**

**आदेश बोर्ड से पारित**

**05/07/2022**

1. यह रिट याचिका दिनांक 19.12.2019/02.01.2020 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा में उनकी जन्म तिथि में सुधार के लिए दावा आवेदन को प्रत्यर्थीगण द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी क्र. 04 विद्यालय से वर्ष 2014 में 10 वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी । उक्त 10 वीं कक्षा की मार्कशीट में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि "14.06.1997" दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह एक गलत प्रविष्टि है जो 10 वीं बोर्ड परीक्षा में दर्ज की गई है, जबकि उसकी वास्तविक जन्म तिथि **"14.06.1998"** है।

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि 10 वीं कक्षा की मार्कशीट को छोड़कर, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य, दोनों के उपलब्ध अन्य सभी अभिलेखों में, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि **"14.06.1998"** के रूप में परिलक्षित होती है और दर्ज की गई है । यह वह सुधार है जिसकी याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण से मांग की जा रही है । यह वह अनुरोध है जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **जिज्ञा यादव बनाम सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और अन्य (2021) 7 एसएससी 535** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत पर बहुत भरोसा किया है ।

5. याचिका का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी क्र. 1, 2 और 3 के ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार वर्ष 2019 में 5 साल से अधिक समय के बाद अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए अनुरोध

किया है, जबकि 10 वीं बोर्ड परीक्षा का उसका परिणाम वर्ष 2014 में ही प्रकाशित किया गया था ।

6. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के अनुसार, उनके पास प्रमाण पत्र में जन्म तिथि और लिपिकीय त्रुटि, यदि कोई हो, को सुधारने के लिए एक तंत्र है, लेकिन जिसके लिए संबंधित आवेदक को क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियमों में विहित निर्दिष्ट समय के भीतर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना होगा। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के अनुसार, मार्कशीट में सुधार के लिए दिया गया समय 5 साल का है। वर्तमान मामले में, चूंकि आवेदन को उस निर्धारित पांच साल के समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थियों ने क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियमन के संदर्भ में इसे खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस अवसर पर **जिज्ञा यादव (पूर्वोक्त)** के उस निर्णय पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 167 से 173 में उप-विधियों से संबंधित और आगे पैराग्राफ 200 से 205 और 207 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> **"167.** शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि परिवर्तनों की कुछ विशेषताएँ हैं जो छात्र आमतौर पर अपने प्रमाण पत्रों में दर्ज होने के लिए आवेदन करते हैं। छात्र/पिता/माता का नाम बदलना, छात्र/पिता/माता के नाम में सुधार और जन्म तिथि में सुधार प्राथमिक हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक ही पैमाने पर नहीं मापा जा सकता है। यहां तक

कि उपनियमों में भी, ये सभी परिवर्तन प्रतिबंधों/शर्तों के एक ही सेट के अधीन नहीं हैं और अलग-अलग परिवर्तन अलग-अलग शर्तों द्वारा सीमित हैं।

**168.** नाम या जन्म तिथि में "सुधार" के संबंध में शर्तें उतनी सख्त नहीं हैं जितनी कि उसके परिवर्तन पर लागू शर्तें हैं। नाम में सुधार के लिए, 2018 के उपनियम पांच साल की सीमा अवधि प्रदान करते हैं और ऐसे सुधारों की अनुमति देते हैं जिन्हें स्कूल के रिकॉर्ड की तुलना में टाइपोग्राफिक, तथ्यात्मक या वर्तनी की त्रुटि के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। जाहिर है, एक सुधार का मतलब होगा कि मूल रिकॉर्ड को मामूली संशोधन के साथ बनाए रखना ताकि इसे स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप बनाया जा सके। संशोधन की यह आवश्यकता विभिन्न कारणों से पैदा हो सकती है, अर्थात् प्रकाशन के समय टाइपोग्राफिक गलती, वर्तनी त्रुटि या तथ्यात्मक त्रुटि अर्थात् तथ्य की एक त्रुटि जैसा कि उस समय मौजूद था जब प्रमाणपत्र प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार, स्कूल रिकॉर्ड (जैसा कि वे बोर्ड को जानकारी भेजने के समय मौजूद थे) और सीबीएसई प्रमाण पत्रों के बीच समानता लाने के लिए नाम में सुधार किया जाता है। हालांकि, अगर बाद में स्कूल रिकॉर्ड में बदलाव किया जाता है और बोर्ड को अद्यतन स्कूल रिकॉर्ड के आलोक में अपने प्रमाण पत्रों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है, तो इसे सुधार नहीं कहा जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है, लेकिन यह परिवर्तन दर्ज करने की प्रकृति में होगा। इसलिए, एक "सुधार" से काफी हद तक विचलन करते हुए, उपनियम नाम को "बदलने" का विकल्प प्रदान करते हैं, जो विभिन्न शर्तों के अधीन है।

**169.** इसी तरह का प्रावधान या तो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर या अदालत के आदेश के आधार पर जन्म तिथि में "सुधार" के लिए उपलब्ध है। "परिवर्तन" शब्द का उपयोग जन्म तिथि के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम के विपरीत, केवल एक ही जन्म तिथि हो सकती है और इसे स्कूल के रिकॉर्ड या न्यायालय के आदेश के अनुरूप बनाने के लिए केवल एक सुधार किया जा सकता है। इसे अपनी पसंद की नई तारीख के साथ पूर्व को बदलने के लिए नहीं बदला जा सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि जन्म तिथि और नाम में सुधार से संबंधित प्रावधान न्यायसंगत और उचित हैं और सुधारों की अनुमति पर कोई अनुचित प्रतिबंध लागू नहीं करते हैं। सीमा अवधि के संबंध में प्रतिबंध की जांच अन्य प्रावधानों के साथ बाद में की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**170.** नाम के "परिवर्तन" का प्रावधान कहीं अधिक कठोर है और सही स्थिति को तय करने के लिए पूरी तरह से समीक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान कानून के अनुसार, दो पूर्व शर्तों को पूरा करने पर नाम परिवर्तन की अनुमति है-कानून की अदालत की पूर्व अनुमति और

आधिकारिक राजपत्र में प्रस्तावित परिवर्तन का प्रकाशन। ये शर्तें एक अन्य शर्त के साथ सह-अस्तित्व में हैं जो निगमित करती हैं कि परिणाम के प्रकाशन से पहले पूर्व अनुमति और प्रकाशन दोनों किए जाने चाहिए। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि उम्मीदवार के परिणाम के प्रकाशन के बाद नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, भले ही इसकी अनुमति न्यायालय द्वारा दी गई हो और इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो। दूसरे शब्दों में, एक बार उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाने के बाद, बोर्ड केवल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम में सुधार की अनुमति देगा। इसके अलावा, स्वतंत्र इच्छा से नाम बदलने से इनकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**171.** विशेष रूप से, हमारे सामने मामले अलग-अलग अवधियों से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सी.बी.एस.ई. के 2007 से पहले मौजूद उपनियम अलग थे। 2007 से 2018 तक की परीक्षा उपनियमों की यात्रा का सारांश अब तक सारणीबद्ध किया गया है। "सुधार" और "परिवर्तन" के बीच का अंतर हमेशा 2007 से पहले सहित अच्छी तरह से सीमांकित किया गया था। जहां तक सुधार का संबंध है, जिसका अर्थ इसे स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन करना हो सकता है, लेकिन जब उम्मीदवार या उसके माता-पिता का नाम बदलने का अनुरोध करने की बात आती है, तो यह उसके लिए निर्दिष्ट पूर्व शर्तों का पालन करने के बाद ही किया जा

सकता है। हालांकि, जब जन्म तिथि में बदलाव की बात आई तो यह पूरी तरह से प्रतिबंधित था। केवल जन्म तिथि के संबंध में सुधार को स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाने की अनुमति दी गई थी और जिसके लिए परिणाम की घोषणा से दो साल की सीमा निर्दिष्ट की गई थी। दो साल की आवश्यकता को अनुचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। उम्मीदवार और उसके माता-पिता से सतर्क रहने और उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उपचारात्मक उपाय करने की अपेक्षा की जाती है। वह भी स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाए जाने के लिए। बोर्ड को स्कूल रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को जारी रखने के अनुशासन का पालन करना चाहिए क्योंकि यह उम्मीदवार द्वारा कैरियर के अवसरों सहित आगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रूप से, 2007 से पहले प्राप्त स्थिति में किसी भी समय सीमा का प्रावधान नहीं था जिसके भीतर उम्मीदवार के नाम या उसके माता-पिता के नाम में सुधार किया जाना था। ये प्रतिबंध निश्चित रूप से उचित प्रतिबंध हैं, जबकि संबंधित उम्मीदवार को जारी किए गए प्रमाण पत्रों के रूप में अपने रिकॉर्ड को बदलने के लिए बोर्ड की सक्षम शक्ति को मान्यता देते हुए इसे स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप या अन्यथा बनाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**172.** यह देखने के लिए पर्याप्त है कि प्रासंगिक अवधि के लिए विभिन्न प्रावधानों के लिए उपनियमों में बार-बार संशोधन किए गए हैं। अंतिम निर्देशों की प्रकृति के लिए जो हम जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, समय-समय पर संशोधित संबंधित उपनियम की वैधता पर विस्तार करना आवश्यक नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपनियम दो अलग-अलग व्यवस्थाओं को मान्यता देता है। प्रथम यह है कि मूल प्रमाण पत्र में संशोधन करना है ताकि इसे पदधारी के स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप बनाया जा सके। दूसरा है कि मूल प्रमाण पत्र में उन विवरणों को शामिल करना है जो स्कूल के रिकॉर्ड से अलग हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**173.** निर्विवाद रूप से, उम्मीदवार आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा और सीबीएसई बोर्ड सहित स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य के कैरियर के अवसर तलासेगा। सीबीएसई मूलभूत दस्तावेजों जो स्कूल दस्तावेज हैं, के आधार पर उम्मीदवार के संबंध में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है । इसलिए, सीबीएसई यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुधार करने के लिए बाध्य है कि सीबीएसई प्रमाणपत्र स्कूल के रिकॉर्ड में दी गई प्रासंगिक जानकारी जो प्रासंगिक समय पर मौजूद थी और भविष्य में बदलाव जिसमें सीबीएसई द्वारा परिणामों के प्रकाशन के बाद भी शामिल है, के अनुरुप है । हालांकि, जब सीबीएसई द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र में

किसी भी जानकारी को दर्ज करने की बात आती है, जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, तो यह आवश्यक है कि सीबीएसई को सार्वजनिक दस्तावेज का समर्थन करने के लिए जोर देना चाहिए, जिसका अनुमानित मूल्य है और इस तरह के प्रकरण में बदलाव को शामिल करने के लिए अदालत द्वारा की गई घोषणा होनी चाहिए । उस संबंध में, सीबीएसई उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन के अनुसरण में उसके द्वारा शामिल किए गए परिवर्तनों के कारण किसी तीसरे पक्ष/निकाय द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ खुद को आश्वस्त करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकता है। समापन पैराग्राफ में, हम इस फैसले में चर्चा के आलोक में सीबीएसई बोर्ड को निर्देश जारी करने का इरादा रखते हैं। समान निर्देशों की प्रकृति के लिए, जिन्हें हम जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि विचाराधीन मामलों में किसी भी असंगत दृष्टिकोण को रोका जा सके, जिसमें सीबीएसई बोर्ड द्वारा निपटाए जाने वाले भविष्य के मामले भी शामिल हैं, हमारे लिए समय-समय पर प्रभावी प्रासंगिक उपनियमों में संबंधित संशोधनों की वैधता के प्रश्न पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**200.** जो भी हो, हमें मोहम्मद सरिफुज़ ज़मान[77] के प्रकरण में इस न्यायालय के कथन की जांच करनी चाहिए । इस मामले में जन्म तिथि में लिपिकीय प्रकृति के सुधार का अनुरोध शामिल था ताकि

इसे सही स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप लाया जा सके । पैराग्राफ 3 इस प्रकार नोट करता हैः

"3. उत्तरदाताओं में से एक, एक छात्र, जिसने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा ली थी, ने वर्ष 1991 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद, उसने उच्च माध्यमिक परीक्षा और फिर वर्ष 1998 में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। जब उसने रिट याचिका दायर की, तो वह कंप्यूटर कोर्स में अध्ययन कर रहे थे। उस समय, 12.10.1999 को, उन्होंने बोर्ड को एक आवेदन दिया जिसमें शिकायत की गई थी कि उनकी जन्म तिथि गलत तरीके से स्कूल के रिकॉर्ड में 30.05.1974 के रूप में उल्लिखित की गई थी, जबकि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 16.08.1975 थी। गलत जन्म तिथि, जैसा कि स्कूल द्वारा अग्रेषित की गई थी, बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र में आ गई थी। रिट याचिकाकर्ता छात्र ने दलील दी कि उसे स्कूल के रिकॉर्ड में सही जन्मतिथि दर्ज किये जाने के महत्व का एहसास नहीं था, और इसलिए, जब तक उसे आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया, तब तक उसे इसके निहितार्थ का भी एहसास नहीं था। प्रत्यर्थी द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्कूल के प्रधानाचार्य को दिया गया आवेदन उसके द्वारा बोर्ड को भेज दिया गया था। प्रधानाचार्य ने उल्लेख किया कि प्रत्यर्थी की आयु प्रवेश रजिस्टर और अन्य स्कूल रिकॉर्ड में 16.08.1975 दर्ज की गई थी, लेकिन यह गलती से था कि बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय जन्म तिथि गलत तरीके से 30.05.1974 दर्ज कर दी गई थी। प्रधानाचार्य ने गलती को "लिपिकीय" बताया और इसे सुधारने की अनुशंसा की। चूंकि बोर्ड ने आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**201.** न्यायालय असम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए विनियमों पर विचार कर रही थी, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों में सुधार करने के लिए परिणाम की घोषणा के बाद 03 वर्ष का समय प्रदान किया गया है 77 पूर्वोक्त फुटनोट संख्या 16 वर्ष । छात्र ने तीन साल की समाप्ति के बाद बोर्ड का दरवाजा खटखटाया और इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न केवल यह था कि क्या तीन वर्षों की अवधि विनियमों के अनुसार लागू की जाएगी या कोई छूट दी जा सकती है। न्यायालय ने यह कहते हुए कोई छूट देने से इंकार कर दिया कि परिसीमा अवधि की समाप्ति उपचार को समाप्त कर देगी। पैराग्राफ 12 में, यह इस प्रकार नोट करता हैः-

"12. विलंब विवेक को हरा देती है और सीमा का नुकसान उपचार को ही नष्ट कर देता है। अवधि बीत जाने के रुप में विलंब का परिणाम साम्या के सिद्धांत पर विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के इंकार के रुप में होता है। परिसीमा का नुकसान के परिणामस्वरूप उपचार से वंचित होना, सार्वजनिक नीति और उपयोगिता पर आधारित एक सिद्धांत है, न कि केवल साम्या पर। समय की एक सीमा होनी चाहिए जिसके द्वारा मानव मामले हल हो जाते हैं और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। नियम 8 गलत गणना या लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जन्म तिथि में सुधार करने के लिए आवेदक को अधिकार तथा बोर्ड को दायित्व के साथ शक्ति प्रदान करता है। स्कूलों के निरीक्षक के माध्यम से आवेदन को संसाधित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो स्कूल के रिकॉर्ड को सत्यापित करेगा और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि नियम 8 के ढांचे के भीतर अनुमत दावों के अलावा अन्य दावों को विचार से बाहर रखा जा सके। सुधार के लिए आदेश पारित करने की शक्ति बोर्ड के सचिव जैसे उच्च पदाधिकारी के पास निहित है। केवल प्रमाण पत्र लिखने के चरण में एक अशुद्धि, हालांकि अन्य सभी पूर्व दस्तावेज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी मामलों में सही हैं, प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर ठीक होने में सक्षम है।"

**202.** तब इसने तीन साल की अवधि को एक उचित समय माना क्योंकि यह एक छात्र के लिए अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी त्रुटि को नोटिस करने के लिए पर्याप्त समय है। पैराग्राफ 13 इस प्रकार नोट करता हैः

"13. विनियमन द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि एक बहुत ही उचित अवधि है। प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को ही संबंधित छात्र को प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टियों के बारे में सूचित हो जाना चाहिए । हर किसी को उनकी उम्र और जन्म तिथि याद रहती है। प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि सही नहीं है, यदि ऐसा है, तो प्रमाण पत्र उसके हाथों में आने के बाद छात्र को कुछ ही समय के भीतर एहसास होगा । प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक किसी शैक्षणिक संस्थान में कहीं और प्रवेश लेगा या नौकरी या करियर की तलाश कर सकता है जहां उसे अपनी उम्र और जन्म तिथि का उल्लेख करना होगा। यदि वह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को त्रुटि को नोटिस करने में विफल रहता है, तो भी उसे इसके तुरंत बाद पता चल जाएगा। इस प्रकार, विनियमन 3 द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्धारित तीन वर्षों की अवधि काफी उचित है। यह मुकदमा दायर करने के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करने जैसा कुछ नहीं है। तीन वर्ष का प्रिस्क्रिप्शन एक विभाजन रेखा निर्धारित कर रहा है जिसके पहले सुधार करने के लिए बोर्ड की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए और जिसके बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता है। यदि विलंबित आवेदनों को प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और हो सकता है कि साक्ष्य खो गए हों। ऐसे साक्ष्य-यहां तक कि सुविधाजनक साक्ष्य-अस्तित्व में लाए जा सकते हैं जो जांच की अवहेलना कर सकते हैं। तीन साल का प्रिस्क्रिप्शन का प्रतिबंध ऐसी सभी स्थितियों का ध्यान रखता है। यह प्रावधान न तो अवैध है और न ही अधिनियम की धारा 24 के दायरे से बाहर है और इसे मनमाना या अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि के भीतर सुधार की मांग करने वाले आवेदक स्वयं एक वर्ग बनाते हैं और इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन का इच्छित उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के परिप्रेक्ष्य में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**203.** यह देखा जा सकता है कि एक पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अलावा, न्यायालय मोहम्मद सरिफुज़ ज़मान[78] के प्रकरण में एक वैधानिक कानून की छत्रछाया में लिपिकीय गलतियों को सुधारने के लिए सीमा अवधि की तर्कसंगतता के एक बहुत ही संकीर्ण प्रश्न से निपट रहा था। न्यायालय के पास उन परिस्थितियों से निपटने का कोई अवसर नहीं था जिनमें कोई व्यक्ति संविधान के अधीन अपने गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना नाम बदलना चाहेगा। न्यायालय इसे विशुद्ध रूप से नागरिक लेन-देन के रूप में देख रहा था और वास्तव में, सीमा की समाप्ति कैसे उपचार को पूरी तरह से बाधित करेगी, इस बारे में बात करते हुए इसे ऐसा ही माना। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, हम दोहराते हैं कि हम नागरिक कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकारों और संविधान के तहत मौलिक माने जाने वाले और संरक्षित अधिकारों के बीच अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार के प्रयोग को उचित आधार पर विनियमित किया जा सकता है, लेकिन एक मजबूत और वैध उद्देश्य के बिना पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है। सिवाय इसके कि मोहम्मद सरिफुज़ ज़मान 79 में दिया गया निर्देश उक्त मामले में विशिष्ट तथ्यों से संबंधित है और यह भी कि उस मामले में वास्तव में छात्र के प्रति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई पूर्वाग्रह नहीं था (परिवर्तनों की वैसे भी अनुमति थी) हम और कुछ नहीं कहते हैं।

**<u>निष्कर्ष और सी०बी०एस०ई० को निर्देश</u>**

204. यद्यपि हमने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है, अंतिम विश्लेषण में समाधान की आवश्यकता वाला वास्तविक विवाद सुधार या परिवर्तन की प्रकृति के बारे में है, जैसा भी मामला हो, पूर्व छात्र सहित छात्र के कहने पर सीबीएसई द्वारा अनुमति दी जा सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मोटे तौर पर, दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

205. प्रथमतः जहां पदधारी चाहता है कि सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में "सुधार" स्कूल रिकॉर्ड में उल्लिखित विवरणों के अनुरूप किया जाए जैसा कि हमने माना है कि सीबीएसई के लिए इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने या किसी भी पूर्व शर्त को संलग्न करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय उचित अवधि की सीमा के और उस अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सीबीएसई को मौजूदा नियमों के तहत अपना रिकॉर्ड बनाए रखना है। ऐसा करते समय, यह निश्चित रूप से पदधारी द्वारा अन्य शर्तों के अनुपालन के लिए जोर दे सकता है, जैसे कि, आवश्यक घोषणा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करना और इस तरह के सुधार के कारण तीसरे पक्ष द्वारा उसके खिलाफ किसी भी दावे से सीबीएसई को क्षतिपूर्ति करना।

सीबीएसई द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र (या डुप्लिकेट मूल प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो) के समर्पण/वापसी के लिए जोर देना उचित होगा, जिसे किए गए परिवर्तनों और इस तरह के सुधार की तारीख के खिलाफ कैप्शन/एनोटेशन के साथ आवश्यक सुधार करने के बाद जारी किए जाने वाले नए प्रमाण पत्र के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। नाम में सुधार के मामले के अलावा यह मूल प्रविष्टियों को बरकरार रख सकता है क्योंकि यह विस्मृत होने के अधिकार के प्रयोग में है । नए प्रमाण पत्र में यह घोषणा भी हो सकती है कि मूल सीबीएसई प्रमाण पत्र में सुधार दर्ज करने के अनुरोध के समर्थन में पदधारी द्वारा प्रस्तुत स्कूल रिकॉर्ड की वास्तविकता के लिए सीबीएसई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सी.बी. एस.ई. नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के बदले में पदधारी द्वारा उचित निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर भी जोर दे सकता है। साथ ही, सीबीएसई केवल परिणाम के प्रकाशन से पहले स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप सुधार के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त लागू नहीं कर सकता है। इस तरह की स्थिति, जैसा कि हमने माना है, अनुचित और अत्यधिक होगी। हम दोहराते हैं कि यदि सुधार दर्ज करने के लिए आवेदन स्कूल के रिकॉर्ड पर आधारित है जैसा कि सीबीएसई द्वारा परिणामों के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने के समय प्राप्त किया गया था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तो यह सीबीएसई के लिए उचित सीमा अवधि प्रदान करने के लिए खुला होगा जिसके भीतर उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार दर्ज करने के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, यदि परिवर्तन दर्ज करने का अनुरोध सीबीएसई द्वारा परिणामों के प्रकाशन और प्रमाण पत्र जारी करने के बाद बदले गए स्कूल रिकॉर्ड पर आधारित है, तो उम्मीदवार सीबीएसई द्वारा निर्धारित उचित सीमा अवधि के भीतर इस तरह के परिवर्तन को दर्ज करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। इस स्थिति में, उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसा परिवर्तन स्पष्ट रूप से उसके कहने पर होगा। यदि वह स्कूल रिकॉर्ड के सुधार के लिए ऐसा आवेदन करती है, तो उससे स्कूल रिकॉर्ड के संशोधित होने के तुरंत बाद सीबीएसई में आवेदन करने की उम्मीद की जाती है और जो उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। वास्तव में, मौजूदा नियमों के तहत आधिकारिक रिकॉर्ड के संरक्षण की अवधि समाप्त होने और संबंधित उम्मीदवार का कोई रिकॉर्ड पता लगाने योग्य नहीं होने या उसका पुनर्निर्माण नहीं होने की स्थिति में सीबीएसई आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। स्कूल अभिलेखों के बाद के संशोधन के मामले में, यह नाम परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की गई पसंद सहित विभिन्न कारणों से हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है। दूसरे शब्दों में सीबीएसई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सुधार दर्ज करने के लिये अनुरोध को सीबीएसई के परीक्षा परिणामों के प्रकाशन से पहले किए गए आवेदन तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।

207. उपरोक्त के आलोक में, हम अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सीबीएसई को विचाराधीन मामलों में उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में, जैसा भी मामला हो, सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदनों को संसाधित करने का निर्देश देते हैं। यहां तक कि ऐसे अनुरोध के लिए अन्य लंबित आवेदनों और भावी आवेदनों पर भी उसी तरह और विशेष रूप से पैराग्राफ 170 और 171 में अब तक दर्ज किए गए निष्कर्ष और निर्देशों पर, जो प्रासंगिक उपनियमों के संशोधन तक लागू हो, कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई अपने प्रासंगिक उपनियमों में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा ताकि उसके द्वारा पहले से जारी या जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों में सुधार या परिवर्तन दर्ज करने के लिए उल्लिखित तंत्र को शामिल किया जा सके ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त निर्णयाधार जो स्पष्ट रूप से निकाला गया है, वह यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत दृढ़ता से अभिनिर्धारित किया है कि जहां यह किसी त्रुटि का सुधार है, वहां प्राधिकारी बिना किसी ठोस कारणों के इसे अस्वीकार नहीं कर

सकते हैं, विशेष रूप से समय-सीमा के आधार पर और विशेष रूप से उस कारण के लिए जिसका उम्मीदवार के आगे के शैक्षिक और आगे के कैरियर के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ।

9. वर्तमान मामले में, अभिलेखों का अवलोकन और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों से जो परिलक्षित है, वह यह है कि 10 वीं कक्षा की मार्कशीट, याचिकाकर्ता की अन्य सभी मार्कशीट और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड, वैधानिक और गैर-सांविधिक में एक अलग जन्मतिथि **"14.06.1998"** है और यह केवल 10 वीं कक्षा की मार्कशीट में जन्म तिथि "14.06.1997" के रूप में दर्शित है । इसके अलावा जो भी परिलक्षित होता है, वह यह है कि सीमा अवधि को छोड़कर, प्रत्यर्थी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है और ऐसा दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता ने केवल तीन महीने की देरी के साथ प्रत्यर्थी अधिकारियों से संपर्क किया है क्योंकि उसका आवेदन पांच साल और तीन महीने की अवधि के बाद दायर किया गया था और जन्म तिथि के सुधार के लिए स्वयं प्रत्यर्थियों के द्वारा पांच साल की अवधि अनुज्ञेय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की इस स्तर यह राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां याचिकाकर्ता का मामला उत्तरदाताओं द्वारा जहां तक, कक्षा 10 वीं अंकसूची में

उसकी जन्म-तिथि के सुधार से संबंधित है विलंब के पहलू को छोड़कर उत्तरदाता-प्रतिष्ठान में लागू अन्य प्रक्रियाओं के अनुसार पुनर्विचार की अपेक्षा करता है।

11. इसलिए उस सीमा तक रिट याचिका स्वीकार होने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है और उपरोक्त सीमा तक आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को अपास्त/रद्द कर किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीमा के पहलू को नजरअंदाज करते हुए गुण-दोष के आधार पर नये सिरे से उचित निर्णय लेने के लिए मामले को उत्तरदाता नं. 01 से 03 के समक्ष फिर से रखने का आदेश दिया जाता है । इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों की सीमा के भीतर एक उचित निर्णय लिया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को नए सिरे से प्रत्यर्थियों से संपर्क करना होगा और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अपनी मूल मार्कशीट को समर्पण करना होगा।

13. उपरोक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान रिट याचिका स्वीकृत एवं निराकृत।

सही/-
(पी०साम कोसी)
**न्यायाधीश**